प्रेस विज्ञप्ति

24 नवंबर, 2020; नई दिल्ली

झारखंड को कोयला खनन क्षेत्रों के जस्ट ट्रांज़िशन की योजना बनानी चाहिए जिससे आने वाले समय में भारी सामाजिक-आर्थिक व्यवधानों से बचा जा सके, यह कहना है आईफॉरेस्ट (iFOREST) द्वारा जारी भारत के कोयला खनन क्षेत्रों में जस्ट ट्रांज़िशन पर पहला अध्ययन।

- पुस्तक – "*जस्ट ट्रांज़िशन इन इंडिया: एन इन्क्वाइरी इंटू द चैलेंजेस एंड ऑप्पोर्टुनिटी फॉर ए पोस्ट कोल फ्युचर*" - इस बात पर प्रकाश डालती है कि क्यों कोयले पर झारखंड जैसे निर्भर राज्य को अपने खनन जिलों के लिए जस्ट ट्रांज़िशन पर योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे अगले 2-3 दशकों में कोयला खनन बंद होने की स्थिति में होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
- आईपीसीसी (IPCC) के अनुसार, 1.5° C तापमान वृद्धि से नीचे रहने के लिए कोयला आधारित पावर प्लांट को 2050 तक चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाना चाहिए।
- थर्मल पावर प्लांट पहले से ही तेजी से घटती नवीकरणीय ऊर्जा लागत, बढ़ती लागत जैसे कि बढ़ती प्रदूषण नियंत्रण लागत एवं के कारण प्रतिस्पर्धी नहीं रहा। बिजली उत्पादन में कोयला की हिस्सेदारी आने वाले दशक में काफी कम हो जाएगी, जिससे कोयले की मांग में कमी आएगी।
- कोयला खदानों से लगातार लाभ में कमी आ रही हैं और खदानें बंद होते जा रही हैं; झारखंड में, 50% खदानें बंद हैं। अधिकांश खदानें बगैर किसी उपयुक्त योजना एवं बिना किसी सामाजिक-आर्थिक पहलु को ध्यान मे रखते हुए बंद की गई है ।
- रामगढ़ जिले में iFOREST द्वारा एक विस्तृत अध्ययन किया गया है। अध्यन में यह पाया गया है कि आधी खदानें बंद हैं, और दो-तिहाई खदानें बिना लाभ के ही परिचालित हैं। रामगढ़ की मौजूदा खदानें अगले 10-20 वर्षों में फेज आउट हो जाएंगी, जिससे जिला आर्थिक विघटन के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाएगा ।
- भारत के ऊर्जा परिवर्तन की योजना का जस्ट ट्रानजिशन के साथ मेल जरूरी है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोयला खनन पर निर्भर लोगों और उदयोगों को नुकसान न हो।
- जस्ट ट्रानजिशन के लिए दुनिया भर में ज़ोर दिया जा रहा है। 2015 के पेरिस समझौते में इसे जलवायु परिवर्तन शमन (क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था है। भारत जस्ट ट्रानजिशन के लिए नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है और एक ठोस नीति और रोडमैप विकसित कर सकता है।

नई दिल्ली, 24 नवंबर, 2020: इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST), नई दिल्ली स्थित पर्यावरण गैर-लाभकारी थिंक टैंक ने भारत के लिए जस्ट ट्रांजिशन के क्या मायने है, यह समझने के लिए पहला ऑन-ग्राउंड अध्ययन प्रकाशित किया है। अध्यन में झारखंड के शीर्ष कोयला उत्पादक रामगढ़ जिले के गहन सर्वेक्षण का विवरण है । ग्राउंड स्टडी के आधार पर कोयले के फेज आउट होने के खतरों और अवसरों को विस्तृत तौर पर बताया है और, जस्ट ट्रानजिशन के लिए एक नीति और प्लानिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव है।

"जस्ट ट्रांज़िशन इन इंडिया: एन इन्क्वाइरी इंटू द चैलेंजेस एंड ऑप्पोर्टुनिटी फॉर ए पोस्ट कोल फ्युचर" - : पुस्तक का विमोचन झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा आज ऑनलाइन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में किया गया । प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री रघुनाथ अनंत माशेलकर उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि थे।

पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर बोलते हुए, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा,
"हमे इस बात पर ध्यान है कि कोयला समय के साथ कम हो जाएगा, और इसलिए हमें भविष्य के लिए कोयला रहित योजना बनानी होगी। चूंकि झारखंड अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, हम अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहे हैं और पर्यटन, वानिकी, कृषि-आधारित उद्योगों और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। जस्ट ट्रांज़िशन राज्य सरकार के विचार करने हेतू एक अच्छा प्लानिंग फ्रेमवर्क है। मैं इस तरह की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लाने के लिए iFOREST को बधाई देना चाहता हूं। "।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, iFOREST के अध्यक्ष, चंद्र भूषण ने कहा कि "भारत के लिए जस्ट ट्रांज़िशन एक अनिवार्यता है । हमारे पास कोयला आधारित ऊर्जा को फेज आउट करने के लिए केवल 20-30 वर्ष है, जिससे जलवायु परिवर्तन के भयावह प्रभावों से बचा जा सकेगा। कोयला खनन क्षेत्रों और कोयले पर निर्भर उद्योगों के परिवर्तन के लिए यह बहुत कम समय है। अगर हम पोस्ट-कोल प्लान अभी बनाना शुरू नहीं करते हैं, तो हमारे कोयले पर निर्भर क्षेत्र आने वाले वर्षों में बड़े आर्थिक और सामाजिक व्यवधानों का सामना कर सकते है।

2015 पेरिस जलवायु समझौता में जस्ट ट्रांज़िशन को शामिल किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोयले के फेज-आउट होने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर श्रमिकों और स्थानीय समुदायों को नुकसान न हो। इसलिए, जस्ट ट्रांज़िशन का मूल उन लोगों के लिए अच्छे काम के अवसरों और सामाजिक समर्थन प्रणालियों को सुनिश्चित करना है, जिनकी आजीविका ऊर्जा परिवर्तन के कारण प्रभावित होंगी।

ऊर्जा और औद्योगिक विकास के लिए देश की सबसे ज्यादा निर्भरता कोयले पर रही है । इस वजह से भारत ने अब तक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयला फेज-आउट और जस्ट ट्रांज़िशन पर काम नहीं किया है।

कोयला आधारित ऊर्जा के मुक़ाबले कम लागत वाले नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार तेजी से हो रहा है । और सौर एवं वायु ऊर्जा से 24x7 बिजली की आपूर्ति अब एक वास्तविकता बन रही है। ऐसी स्थिति में,

देश में कोयले की खपत 2030 तक अपने चरम पर रहने का अनुमान है और फिर जाकर घटने का। इससे कोयला खनन क्षेत्रों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कोयला खदानें बंद हो जाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर और आय में कमी आएगी।

लेकिन कोयला खदानें पहले से ही विभिन्न कारणों एवं घाटे की वजह से अनियोजित तरीके से बंद हो रही है। iFOREST द्वारा अध्ययन यह बताता है कि झारखंड में, 50% खदानें बंद हैं, और परिचालित खदानों में से आधे बिना लाभ के चल रहे हैं। अधिकांश खदानों को बिना किसी उपयुक्त योजना एवं सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए बंद किया गया है । रामगढ़ जिले की स्थिति, जिसे पुस्तक में विस्तार से दर्शाया गया है, यह बताता है कि "क्यों जस्ट ट्रांज़िशन भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की एक चुनौती है।"

रामगढ़ झारखंड के शीर्ष कोयला उत्पादक जिलों में से एक है, लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि इसकी खनन गतिविधियां कम हो रही है। लगभग 50% खदानें बंद हैं, और दो-तिहाई परिचालित खदानों से लाभ नहीं है । इसके अलावा, रामगढ़ एक आकांक्षी जिला है जिसके सामाजिक-आर्थिक संकेतक खराब है।

"स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है जब कोयले पर जिले की आर्थिक निर्भरता को हम समझने की कोशिश करते हैं। कोयला खनन और कोयला पर निर्भर उद्योग, जिले की जीडीपी का लगभग 40% योगदान करते हैं। इसके अलावा, एक-चौथाई परिवार आय के लिए सीधे तौर पर कोयला उद्योग पर निर्भर रहते, जिसमे ज्यादातर अनौपचारिक श्रमिक हैं। जस्ट ट्रांजिशन की योजना के बिना, जिला पहले से भुगत रहा है तथा आने वाले वर्षों में और भी नुकसान होगा।"- श्रुति अग्रवाल, प्रोग्राम एसोसिएट, iFOREST ने कहा।

रामगढ़ सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. आय के लिए लोगों की कोयले पर अत्यधिक निर्भरता है, परंतु यह आय काफी कम होने के साथ अनौपचारिक भी है। लगभग 70% घर, जो कोयले से होने वाली आय पर निर्भर है, 6,000 से 10,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं । ज्यादातर परिवार कोयला इकट्ठा कर के बेचने वाले हैं। केवल 7% ऐसे परिवार है जिनका कोई सदस्य कोयला कंपनियों या कोयला-निर्भर उद्योगों के साथ औपचारिक रूप से काम करता है। इसके अलावा, कोयला खनन में औपचारिक नौकरियां तेजी से घट रही हैं।
2. कोयला खनन पर लोगों की निर्भरता सबसे जाएदा खदानों के आस पास केन्द्रित है । खानों से 10 किमी से अधिक दूर रहने वाले लोग कोयला खदानों पर कम निर्भर हैं।
3. कोयला खनन ने क्षेत्रों में सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम नहीं किया है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के मामले

में जिले की स्थिति बेहद खराब है। इस कारण स्थिति सुधार के लिए, जिले को नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

4. अंत में, कोयला खनन और संबंधित उद्योग पर अत्यधिक ध्यान से अन्य क्षेत्रों के विकास पीछे छूट गए है। रामगढ़ में, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्र काफी प्रभावित हुए हैं। इससे लोगों में यह 'धारणा' बन गयी है कि कोयले की खानों के बिना उनका गुजारा मुश्किल है।

"कोयला खनन क्षेत्रों में लोग दशकों से गरीबी और हाशिये पर हैं। जस्ट ट्रांजिशन इसे दूर करने का एक बड़ा अवसर है। पहले जिले कोयला खनन के कारण प्रभावित थे और अब इसके अनियोजित बंद होने के कारण प्रभावित हैं। हालांकि, अनुभवों से पता चलता है कि जस्ट ट्रांजिशन पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों लिए फायदेमंद हो सकता है, अगर इसे योजनाबद्ध और अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाए, " श्रेष्ठा बनर्जी, सीनियर फेलो, iFOREST ने कहा।

पुस्तक, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जस्ट ट्रांजिशन पर नीतियों और योजनाओं को विकसित करने और वित्तीय संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह भी सिफारिश करती है, कि भारत एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने का नेतृत्व करे जिससे जस्ट ट्रांजिशन का समर्थन विकासशील देशों में किया जा सके।

“जस्ट ट्रांजिशन को क्लाइमेट मिटिगेशन प्लान में केन्द्रित करके, भारत पूरी दुनिया को एक मजबूत संकेत दे सकता है कि वह जलवायु परिवर्तन में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जस्ट ट्रांजिशन से भारत न केवल वैश्विक सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रयास कर सकता, बल्कि कोयला आधारित क्षेत्रों में एक सतत और ठोस अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद कर सकता है । कोयले की खानों को योजनाबद्ध तरीके से बंद किया जाना चाहिए ताकि भारत की ऊर्जा शक्ति प्रभावित न हो, जलवायु लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, और स्थानीय समुदायों को जस्ट ट्रांजिशन से लाभ मिल पाए, ”- चंद्र भूषण

अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क करें, श्रेस्ठा बनर्जी, 9958550622 (srestha@iforest.global)
जस्ट ट्रांजीशन सम्बन्धित अन्य साधन निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://iforest.global/initiatives/energy-climate-change/just-transition/